

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

शुक्रवार, 27 मार्च, 2015/6 चैत्र, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

(2) अतारांकित :

- दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14;
- (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(a), और 10(1) के अन्तर्गत प्राथमिक गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शिका जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-ए(3)-02/2009 दिनांक 01.08.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2014 को प्रकाशित;

- (iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 01.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;
- (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(c,d &e), और 15(2) के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-ए(3)02/2009-1 दिनांक 12.09.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.02.2014 को प्रकाशित;
- (v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकान स्तर की सतर्कता समिति स्थापित करना जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 20.11.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.02.2014 को प्रकाशित; और
- (vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 21.08.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.08.2014 को प्रकाशित।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
 - (i) समिति का 94वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है;

- (ii) समिति का 95वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;
 - (iii) समिति का 96वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 71वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है ; और
 - (iv) समिति का 97वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 73वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का 34वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित की गतिविधियों के समस्तरी अध्ययन पर आधारित है; और
 - (ii) समिति के 79वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है ।
- (3) श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि राजस्व विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का 17वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

(4) श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15), समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि वन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान:-

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान ।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में मुद्रित कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171 004
दिनांक: 26 मार्च, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)